हरिभूमि

शौर्य भूमि

मंडला| अंजिनया | भुआबिछिया | बम्हनीबंजर | नैनपुर | निवास | बीजाडांडी

जबलपुर, गुरुवार 14 मई 2026

login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

मंडला। वन एमपी आर्टिलरी रेजिमेंट एनसीसी जबलपुर द्वारा आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (सीएटीसी) का समापन ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय रांझी, जबलपुर में हुआ। यह शिविर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कीर्ति शिंत्रे एवं लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र शेखावत के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शिविर में शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय मंडला के 71 एनसीसीकैडेट्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कैडेट्स ने ड्रिल, स्पीच, निबंध लेखन, फ्लैगएरिया एवं लाइन एरिया प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कठिन प्रतिस्पर्धाओं मेंअनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय देते हुए विद्यालय को ओवरऑल द्वितीय स्थान दिलाया।इस प्रशिक्षण शिविर में 12 विद्यालयों के कुल 434 कैडेट्स ने भाग लिया।समापन समारोह में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कीर्ति शिंत्रे ने उपविजेता टीम कोट्रॉफी प्रदान कर कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और जज्बे की सराहना की। उन्होंनेभविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कैडेट्स को प्रेरित भी किया।

जिले में स्वरोजगार के लिए 30 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण शुरू

मंडला-मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकामिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 30 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कासंचालन मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड भोपाल द्वारा कियाजाएगा।प्रशिक्षण के दौरान युवाओं एवं महिलाओं को विभिन्न रोजगारमूलक व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें फैंसी डिजाइनिंग, बेसिक सिलाई, मास्टरटेलर, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोग्राफी, मोटर वाइंडिंग, सेंट्रल टेबल डिजाइनिंगसहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुकअभ्यर्थी 13 मई से 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट **http://mpkhadi-gramodyog.com/** पर उपलब्ध है। जिला पंचायत मण्डला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिले के युवाओं सेअधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ने की अपील कीहै।

कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चलाएं विशेषअभियानः कलेक्टर

मंडला। कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्षमें महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय पोषण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कुपोषण उन्मूलन और मातृ-शिशुस्वास्थ्य के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री धोटे ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें।उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी हितग्राहियों कानियमित फॉलोअप करें। साथ ही जिले में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गर्भवती महिलाओं कास्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।कलेक्टर श्री धोटे ने बालिकाओं के वेरिफिकेशन और स्कैनिंग कराने केनिर्देश दिए। स्कैनिंग के पश्चात संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपकर लगातार फॉलोअप सुनिश्चित करने को कहा गया। आयुष विभाग को निर्देशित किया किकुपोषित बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन दवा पिलाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही बच्चों को प्रति 6 माह के अंतराल में एल्बेंडाजोल की दवाखिलाएं और इस संबंध में लोगों को जागरूक भी करें।बैठक में गर्भवती माताओं के खान-पान और पोषण के प्रति उन्हें ागरूक करने पर विशेष बल दिया गया।

कान्हा प्रबंधन और पत्रकारों के बीच बनी सहमतिः नौ दिन से चल रहे धरने पर लगा विराम 14 सूत्रीय मांगों पर सौंपा ज्ञापन

मण्डला।

विगत नौ दिनों से पत्रकारों का चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को समाप्त हुआ। कान्हा प्रबंधन और पत्रकारों के बीच लगभग 2 घंटे चली चर्चा के बाद 14 सूत्रीय मांगो में से अनेक मांगो को पूर्ण किए जाने के बाद धरना समाप्ति की अधिकाधिक घोषणा की गई। पत्रकार कलेक्ट्रेट मार्ग में धरना दे रहे थे बुधवार को कान्हा टाईगर रिजर्व कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया जहां पर 14 बिन्दुओं की जानकारी से प्रबंधन को अवगत कराया गया। इस बैठक में फील्ड डायरेक्टर (प्रबंधक) रविन्द्र मणि त्रिपाठी, डिप्टी डॉयरेक्टर पीके वर्मा, सहायक संचालक आशीष पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहां पर पत्रकारों ने अपनी-अपनी बातें रखते हुए सवाल किए जिसका समाधान किया गया। काफी देर चली चर्चा के बाद पत्रकार सहमत हुए इस दौरान प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा गया।

पत्रकारों की प्रमुख मांगें

धरना दे रहे पत्रकारों ने 14 प्रमुख मांगें प्रशासन और कान्हा प्रबंधन के सामने रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग यह है कि पत्रकारों के पांच सदस्यीय दल को प्रत्येक माह एक बार कान्हा पार्क की मॉनिटरिंग कराई जाए ताकि मीडिया स्वयं जमीनी स्थिति देख सके और सही जानकारी जनता तक पहुंचा सके। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि कई बार कान्हा प्रबंधन मीडिया को अधूरी या गलत जानकारी उपलब्ध कराता है। इसलिए दूसरी प्रमुख मांग यह रखी गई है कि यदि पत्रकारों को गलत जानकारी दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आंदोलनकारियों ने कान्हा के अंदर किए जा रहे पक्के निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पार्क के भीतर होटल, रिसॉर्ट और अन्य स्थायी निर्माण पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि कान्हा के अंदर बने सभी पक्के निर्माण कार्यों की जांच कर उन्हें हटाया जाए।

अतिक्रमण रिसॉर्ट संस्कृति पर सवाल

पत्रकारों ने कान्हा के तीनों प्रमुख गेटों के आसपास बढ़ रहे अतिक्रमण को भी गंभीर मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि पार्क के आसपास अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं जिससे वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। मांग की गई है कि सभी अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाए जाएं। इसके अलावा रिसॉर्ट्स में देर रात तक डीजे, आतिशबाजी और शादी समारोह आयोजित किए जाने का मुद्दा भी आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। पत्रकारों का कहना है कि इससे वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तेज ध्वनि और रोशनी के कारण जानवरों का प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित होता है। इसलिए पार्क क्षेत्र में डीजे, आतिशबाजी और विवाह समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह भी मांग रखी कि कान्हा क्षेत्र को पूरी तरह मांसाहार मुक्त घोषित किया जाए। उनका कहना है कि इससे वन क्षेत्र की स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

स्टाफ को बदलने की मांग

पत्रकारों ने कान्हा प्रबंधन के पूरे स्टाफ को बदलने की मांग भी उठाई है। उनका आरोप है कि वर्तमान व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते नजर आते हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि नए अधिकारियों की नियुक्ति होती है तो प्रबंधन में सुधार संभव हो सकेगा। धरने में शामिल पत्रकारों ने पिछले पांच वर्षों के बजट और खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा, तकनीकी उपकरणों, भोजन, चिकित्सा व्यवस्था और अन्य संसाधनों पर कितनी राशि खर्च हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसके साथ ही कान्हा प्रबंधन द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रचार-प्रसार पर खर्च की गई राशि का भी ब्यौरा मांगा गया है। पत्रकारों का कहना है कि यदि करोड़ों रुपये प्रचार में खर्च किए जा रहे हैं तो उसका वास्तविक लाभ और उपयोग भी जनता के सामने आना चाहिए।

जानकारी सार्वजनिक करने मांग

धरना दे रहे पत्रकारों ने जंगल सफारी व्यवस्था में भी पारदर्शिता की मांग उठाई है। उनका कहना है कि प्रतिदिन कितनी जिप्सियां सफारी में जाती हैं और पार्क के भीतर कौन-कौन से कार्य कराए जा रहे हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने पार्क के प्रमुख गेटों पर सूचना बोर्ड लगाने मांग की है, जिसमें पुल-पुलिया, सडक़ निर्माण, जल व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों की जानकारी दर्ज हो। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।

पशुओं पर रोक लगाने मांग

धरना प्रदर्शन में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि पार्क क्षेत्र में मौजूद कुछ पालतू और बाहरी पशु वन्यजीवों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा कर सकते हैं। पत्रकारों ने मांग की कि ऐसे सभी पशुओं की निगरानी कर उन्हें प्रतिबंधित किया जाए ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही पार्क क्षेत्र में प्लास्टिक डिस्पोजल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है। पत्रकारों का कहना है कि प्लास्टिक कचरा वन्यजीवों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है।

आकांक्षी ब्लॉक नारायणगंज में निर्धारित इंडिकेटर्स पर फोकस करें- कलेक्टर

मंडला

कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में बुधवार को आकांक्षी विकासखण्ड नारायणगंज की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित 5 थीम्स के 38 इंडिकेटर्स पर विशेष फोकस करते हुए नियत समय-सीमा में लक्ष्य हासिल किए जाएं। कमिश्नर जबलपुर को बनाया नोडल अधिकारी कलेक्टर श्री धोटे ने बताया कि आकांक्षी ब्लॉक नारायणगंज के लिए कमिश्नर जबलपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए सभी विभागों को पोर्टफोलियोवार पूरी जानकारी तैयार करनी होगी। नोडल अधिकारी के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, अतः डाटा पूरी सावधानी से तैयार किया जाए।

विभागों के इंडिकेटर्स पर हुई विस्तृत चर्चा

बैठक में कलेक्टर श्री धोटे ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनजातीय कार्य तथा आजीविका मिशन से जुड़े इंडिकेटर्स पर बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति तेज करना है। स्वास्थ्य विभाग को संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और कुपोषण दर मेंसुधार के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों की सक्रियता और पोषण आहार वितरण पर जोर देने को कहा। शिक्षा विभाग को शाला त्यागी बच्चों की संख्या घटाने और लर्निंग आउटकम सुधारने के निर्देश मिले। पीएचई विभाग (जल निगम) को हर घर नल से जल योजना की प्रगति तेज करने को कहा गया।

समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश

कलेक्टर श्री धोटे ने सभी विभागों को इंडिकेटरवार समयबद्ध कार्ययोजना बनाने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नारायणगंज ब्लॉक को आकांक्षी से विकसित ब्लॉक की श्रेणी में लाना है, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शाश्वत सिंह मीना, सहायक कलेक्टरश्री शैलेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉ. डीजे मोहंती, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नीवरकड़े, उपसंचालक पशुपालन श्री उग्रसेन तिवारी, सहायक संचालक महिला एवं बालविकास श्री रोहित बड़कुल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

वनवासी विकास परिषद कलेक्टर से की मुलाकात सौंपा ज्ञापन

मण्डल।

वनवासी विकास परिषद जिला ईकाई मंडला के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नवागत कलेक्टर से मुलाकात करते हुए चर्चा की है। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुभाष बडोले, प्रांत संगठन मंत्री किशोरी लाल यादव, वनवासी विकास परिषद जिला अध्यक्ष कैलाश डेहरिया, आदिवासी जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज मरकाम, जिला संगठन मंत्री राजू कुड़ापे, जनजाति सुरक्षा मंच जिला सहसंयोजक सोनू मरावी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वनवासी विकास परिषद ईकाई मंडला के द्वारा जनजाति समाज के संवैधानिक प्रावधान के साथ वन अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत पट्टा वितरण में चल रही विसंगतियों के निराकरण को लेकर चर्चा की गई है। वहीं एक ज्ञापन सौंपकर जनजातीय छात्रों के लिए संचालित निःशुल्क कोचिंग केंद्र हेतु स्थायी भवन उपलब्ध कराने की मांग की गई। परिषद द्वारा

बताया गया कि जिला मण्डला अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान की जा रही है। वर्तमान में यह कोचिंग केंद्र किराये के भवन में संचालित हो रहा है जिससे छात्रों एवं संस्था दोनों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि परिषद का संचालन केंद्र एकलव्य बालक छात्रावास घुटास रोड़ भुआ बिछिया में संचालित है। संस्था ने प्रशासन से मांग की है कि मण्डला शहर में स्थित किसी रिक्त शासकीय अथवा अंतः व्यावसायिक भवन को किराये पर उपलब्ध कराया जाए ताकि जनजातीय छात्रों को बेहतर वातावरण में शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा मिल सके। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से आने वाले अनेक छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। यदि उपयुक्त भवन उपलब्ध हो जाता है तो अधिक संख्या में विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा तथा उनकी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से संचालित की जा सकेगी।

क्या सरकारी कार्यालयों में जन्मदिन और निजी पार्टियां मनाना वैध है?

मंडला

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला इतना गंभीर है कि सवाल केवल एक जन्मदिन पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक अनुशासन और शासकीय व्यवस्था की साख का बन गया है।

वही सूत्रों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डी.जे. मोहन्ती का जन्मदिन कार्यालय समय में पूरे स्टाफ के साथ धूमधाम से मनाया गया। सरकारी दफ्तर का नजारा ऐसा था मानो कोई निजी होटल, क्लब या रेस्टोरेंट हो। कर्मचारी फाइलों और जनता के काम छोड़कर जश्न में व्यस्त दिखाई दिए, जबकि दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीण और जरूरतमंद लोग घंटों कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं या अधिकारियों की निजी पार्टियों के लिए? जिस स्वास्थ्य विभाग पर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है,

वहीं का मुख्य कार्यालय यदि कामकाज छोड़कर "उत्सव केंद्र" बन जाए, तो फिर आम जनता न्याय और सुविधा की उम्मीद किससे करे? यह घटना केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सिविल सेवा आचरण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने जैसी नजर आ रही है। जब विभाग का मुखिया ही सरकारी समय और कार्यालय की गरिमा का मजाक बनाएगा, तो अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 13 मार्च 2023 को भी इसी कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगे थे कि शाम होते ही कार्यालय "मयखाना" बन जाता है और मांस-मदिरा के साथ जाम छलकाए जाते हैं। उस समय भी मामला चर्चा में रहा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति और आश्वासन दिए गए। आज तक न जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, न किसी जिम्मेदार अधिकारी पर ठोस कार्रवाई सामने आई।

अब जनता पूछ रही है

क्या सरकारी कार्यालयों में जन्मदिन और निजी पार्टियां मनाना नियमों के तहत वैध है? कार्यालय समय में कामकाज ठप्प होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन केवल छोटे कर्मचारियों के लिए है? आखिर पूर्व वायरल मामलों की जांच रिपोर्ट, सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?विडंबना यह है कि एक तरफ आम जनता अस्पतालों में डॉक्टर, दवा और सुविधाओं के लिए भटकती है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार विभागीय कार्यालयों में जश्न और दिखावे की संस्कृति हावी होती जा रही है। यदि समय रहते प्रशासन ने इस तरह की कार्यशैली पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो यह संदेश जाएगा कि मंडला जिले में सरकारी कार्यालय जवाबदेही से नहीं, बल्कि मनमानी और संरक्षण की संस्कृति से संचालित हो रहे हैं।

मंडला यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई, 1811 चालान काटकर वसूले 5.43 लाख रूपए

मंडला

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक श्रीराजेश रघुवंशी के निर्देशन में मंडला यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विशेष हेलमेट अनिवार्यता अभियान चलायागया।

25 अप्रैल से 10 मई तक संचालित इस अभियान के दौरान जिलेभर में बिनाहेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सघन चालानी कार्रवाई की गई। अभियान के

तहत कुल 1811 चालान बनाए गए तथा 5 लाख 43 हजार 300 रूपए समन शुल्कवसूला गया। वहीं 92 प्रकरणों को लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग कोभेजा गया।अभियान के दौरान मंडला यातायात पुलिस एवं जिले के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वाहन चालकों को हेलमेटपहनने, सीट बेल्ट लगाने एवं यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूककिया गया।

पुलिस द्वारा केवल चालानी कार्रवाई ही नहीं की गई, बल्कि स्कूल, कॉलेजएवं सार्वजनिक स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किएगए। इस दौरान नागरिकों को हेलमेट नहीं पहनने से होने वाले गंभीर दुर्घटनाजोखिमों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश रघुवंशी ने आमजन से अपील की है कि वाहनचलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

खबर संक्षेप

सालीचौका क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश हो रहा बेअसर...

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। समीपस्थ सालीचौका क्षेत्र की स्थिति इस तरह देखने मिल रही है कि इस क्षेत्र में मादक पदार्थो का अवैध कारोबार लगातार अपनी गति पकड़ने में कोई कसर नही छोड़ रहा है। बताया जाता है कि शराब के बाद क्षेत्र में अन्य नशीली चीजो की बिक्री में इजाफा होने से युवा पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर आने लगी है? नगर में आसानी से मिलने वाली महॅगी सिगरेटो के फूॅकने के दौरान युवाओं, किशोरो का लगभग नियमित मदिरा पान करने से घरो का माहौल बिगड़नें की जहां शुरूआत हो गयी है, वही शहरवासी भी शहर के युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आने लगे है, मरोसे मंद सूत्रो के अनुसार इन दिनों नशे के कारोबार में नया मोड़ आ गया है तथा तत्वो द्वारा स्मैक तथा अन्य ऐसे नशीले पदार्थ भी बेचे जाने लगे है? जिनका उपयोग युवाओं के घातक है। मगर इसके बाद भी बताया जात है कि इन पदार्थो का पहली बार प्रयोग करने के बाद गरीब, युवा इसके आदी हो जाते है और इन नशीली चीजो के न मिलने से उनका शरीर छटपटाने लगता है विदित हुआ है कि आजकल युवक बेधड़क नशीली दवाओं व इंजेक्शनों का इस्तेमाल कर रहे है और कथित तौर पर नशा करने के लिए उनकी तरफ डबल रोटी के स्लाईस पर आयोडेक्स भी खाया जा रहा है, जागरूक क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शायद पुलिस लिखा पढ़ी सें बचने नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने प्रयास नही कर रही है, जिसका नतीजा है कि नशीली चीजें बिकने से नगर का वातावरण खराब होने के साथ अधिकतर वे युवा बर्बादी की राह पर कदम बढ़ा रहे है जिनके कंधो पर बूढ़े मॉ, बाप, भाई, बहिनो की देख भाल की सीधी जिम्मेदारी है, फिलहाल शहर में नशीली चीजो की बिक्री की रोकथाम की गुहार उठने लगी है, जिसे गंभीरता से सुन पुलिस को अब नशीली चीजो के विक्रय पर रोक लगाना जरूरी हो गया है।

कहीं कुत्तों से न फैल जाए बीमारी...?

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। इन दिनों देखा जा रहा है कि शहर में अधिकतर आवारा कुत्तें खुजली बीमारी की चपेट में जान पड़ रहे है, इससे नगर की गली चौराहों से आने जाने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। वही दूसरी ओर इन बीमार कुत्तों से अन्य कुत्तें तो चपेट में आने से नही चूक रहे है..। बल्कि इंसानों में भी यह बीमारी फैलने की आशंका है..? यूं फैलती है बीमारी-आवार कुत्तों को अमूमन खुजली की बीमारी फंगस, फफूंद तथा पैरासाइट की वजह से होती है, पालतू कुत्तों की समय समय पर सफाई होने से इनमें बीमारी कम पाई जाती है। लेकिन आवारा कुत्तों में सफाई के अभाव में बीमारी ज्यादा होती है जो बातावरण में फैलाता प्रदूषण भी मुख्य कारण है, प्रदूषित पानी पीने या प्रदूषित धूल कण में लेटने से भी खुजली की बीमारी की समस्या पैदा हो रही है। इंसानों को भी खतरा-पशु चिकित्साकों के अनुसार खुजली से पीड़ति कुत्तें बीमारी से परेशान होकर इधर उधर तेजी से घूमतें है, जिससे पास से निकलने वाले लोगों को भी इनके कीटाणु फैलतें है, बच्चों को अधिक सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि बच्चों में नासमझी की वजह से बच्चों के इनके सम्पर्क में आने या छू लेने से उन्हे भी बीमारी लगने की संभावना रहती है। मुहिम चालाई जाए- क्षेत्र में घूमते आवारो कुत्तों में खुजली रोग ज्यादा फैल रहा है, गलियों तथा सड़कों पर घूमतें खुजेरिया कुत्तों से बच्चों को बचाने की चिंता अभिभावकों कों सताने लगी है, शहर के आवारा कुत्तों में तेजी से यह बीमारी फैल रही है, नगरपालिका को पशु चिकित्सालय की सहायता से ऐसे कुत्तों का उपचार करवाकर इन्हें शहर से दूर जंगल में छोड़ा जैसी पहल चलना चाहिए।

नगर में भारी वाहनों पर निर्धारित समय के लिये लागू की जावे नो एन्ट्री

हरिभूमि न्यूज/ सांईखेड़ा। जहां एक ओर सांईखेड़ा क्षेत्र में लगातार विकास की बात तो आये दिन होते हुए सुनी जा रही है, मगर नगर की प्रमुख समस्या को लेकर आज तक निजात दिलाने की ओर किसी भी प्रकार की पहल नही होना जहां क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास के कार्यो पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए देखा जा रहा है? वही दूसरी ओर आम लोगों की जिन्दगी भी इस समस्या के चलते खतरे से खाली दिखाई नही दे रही है, क्योंकि इस समस्या के बीच गरीब लोगों को मौत के मुख्य में बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर देखा जा रहा है? बताया जाता है कि नगर के बीचों बीच से निकला हुआ प्रदेश की राजधानी से जुड़ने वाले स्टैट स्तर के मार्ग पर जिस प्रकार से दिन भर भारी वाहनों की धमाचौकड़ी लगी रहती है, वही दूसरी ओर इस मार्ग के किनारे ही लगने वाले साप्ताहित बाजार में दुकानदारी करने वालों के लिए भी खतरे की घंटी बजाते हुए यह वाहन तेज गति से दौड़ रहे है?

जंगल क्षेत्र की अनेक पंचायतों में शासन की राशि खर्च होने के बाद भी अधूरा पड़े हुये निर्माण कार्य ग्राम विकास की सच्चाई पर खड़े कर रही सवाल

हरिभूमि न्यूज/बारहाबड़ा।

यह बात अलग है कि बीते हुये पंचायत का कार्यकाल बदले हुये नये पंचायतों के गठन को भी चार साल से अधिक का समय बीतने को है। मगर यदि पंचायतों द्वारा जिस तरह विकास कार्यो में नाम पर शासन की राशि की होली खेली गई है उसकी सच्चाई जंगल क्षेत्र के उन गांवों में देखने आसानी से मिल सकती है जहां पर विकास कार्यो के नाम पर पैसा तो खर्च हुआ है। मगर आज भी अनेक पंचायतों में अधूरे पड़े हुये विकास कार्य पंचायत के बीते हुये कार्यकाल से लेकर वर्तमान पंचायत के जनप्रतिनिधियों सहित ब्लाक स्तर पर बैठे हुये अधिकारियों की गफलत बाजी की सच्चाई को उजागर करने से नही चूक रहे है? इस बात की सच्चाई जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाले जंगल पट्टी की अनेक पंचायतों में असानी से देखने मिल सकती है। बताया जाता है कि पंचायतों द्वारा यहां के गांवों में निर्माण कार्यो के नाम पर सरकारी राशि खर्च तो कर डाली है। मगर जिस तरह निर्माण कार्य अधूरे दिखाई देने के साथ साथ चंद दिनों के अंदर टूट चुके है वह सबालों को जन्म देने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाने से नही चूक रहे है..? इतना ही नही बताया जाता है कि इन गुणवत्ता पूर्ण कार्यो जो निर्माण के बाद अपना पहला जन्म दिन तक नही मना पाये है। मगर अधिकारियों की कृपा दृष्टि तथा कमीशन के चक्कर में पुनः सुधार कार्य के नाम पर राशि स्वीकृत होने की चर्चायें सुनाई देने से नही चूक पा रही है..? कुछ इसी प्रकार का हाल स्वच्छता सर्वेक्षण के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि स्वच्छता के नाम पर लाखों रूपया खर्च होने के साथ साथ पंचायतों द्वारा अधिकारियों की मिली भगत से कागजों में जहां ओडीएफ इसके बाद ओडीएफ प्लस रिकार्ड के दस्ताबेजों में नई नबेली दुल्हन की तरह सजाकर जिम्मेदार अधिकारी स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर उत्कृष्ट पुरूस्कार लेने के हकदार बनने में भी कोई कसर नही छोड़ी गई है? मगर इन पंचायतों की सच्चाई इस तरह से देखने मिल रही है कि लोगों के घरों में आज भी अधूरे पड़े हुये शौचालय गफलत बाजी का अधिकारियों को आईना दिखाने से नही चूक रहे है और शौचालय निर्माण के लिये खोदे गये गड्ढे लोगों के लिये कचरादान बन जाने के कारण शोभा की सुपारी बनकर रहे गये है? मगर इस सबके बाद हैरत तो इस बात को लेकर देखने मिल रही है कि जिले से लेकर तहसील स्तर पर देश में आयोजित होने वाली सबसे बुद्विमान दर्ज की परीक्षा को सफल करने अधिकारियों के हाथों में बागडोर होने के बाद भी उनके अधिनस्थ आने वाले क्षेत्रों में इस तरह दौड़ रही गफलत बाजी की रैलगाड़ी को वह खुद ही हरि झंडी दिखाने में पीछे नही है..? यह बात अलग है कि जब जिले से लेकर तहसील स्तर पर बैठे हुये अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया जाता है कि इसकी जानकारी ब्लाक से लेकर पंचायत स्तर के अधिकारियो को पहले ही मिल जाने के चलते वह अपनी पंचायतों को दुल्हन की तरह सजाते हुये अधिकारियों के स्वागत हेतु तैयार तो कर लिया जाता है और इसी के चलते यहां की वास्तविक सच्चाई उजागर होने से बच जाती है? यदि यही सक्षम अधिकारी अचानक बगैर किसी पूर्व सूचना के जंगल क्षेत्र के इन गांवों को अचानक दौरा कर लेवे तो हरिभूमि द्वारा उठाई जाने वाली इस सच्चाई पर मुहर लगने से नही चूक पायेगी..? मगर वह कहाबत है कि थोडे थोड़ में सभी की सोंझआई होती है तो नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को सब कुछ दीप की आग के सामने काली लता भी हरियाली फैलाते हुये शीतलता का प्रसाद बटने से नही चूक पाया है..? जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाली अनेक ग्राम पंचायतों के गांवों का रूख किया जावे तो यहां पर हाई स्कूल से लेकर शमशान घाट सहित शौचालयों तथा बरोबर बांधों के अधूरे पड़े हुये निर्माण कार्य व गांवों में फैल रही गंदगी पंचायतों की सच्चाई उजागर होने से नही चूक पायेगी। वही दूसरी ओर निष्ठावान बनकर उत्कृष्ट पुरूस्कार के लिये ताल ठोकने वाले अधिकारियों की पोल खुलकर सामने आने से नही बच पायेगी..? बताया जाता है कि जंगल क्षेत्र की पंचायतों में सरोबर तालाबों के निर्माण पर लाखों रूपया की राशि खर्च करते हुये दो झुरैईयों के बीच तालाब तैयार करते हुये शासन की राशि का किस तरह पंचायत से लेकर ब्लाक व जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा बंदर बांट किया गया है इस बात की सच्चाई जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में आसानी से देखने मिल सकता है। जहां पर सूखे दिनों में पानी रहने की बात तो दूरे बारिश के दिनों में तक पानी नजर आने की कल्पना करना मुश्किल होने से नही चूकता है..? क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि पंचायतों के पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यो की किसी निष्ठावान अधिकारी से जांच कराई जावे तो सच्चाई अपने आप ही उजागर होने से नही बच पायेगी। मगर सबाल यह पैदा हो रहा है कि जब अधिकारी अपने चैम्बरों से निकला ही नही चहेगे तो फिर इनकी जांच करेगा कौन..? वही यदि मान लिया जावे कि जब कभी कही किसी पंचायत या क्षेत्र का निरीक्षण करने की औपचारिकता निभाई जाती है तो वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों को पहले से ही सूचना देकर पहुंचने के चलते गफलत बाजी की सच्चाई आंखों से ओझल होने से नही चूक पाती है..। इसी का परिणाम है कि जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते ब्लाक स्तर से लेकर पंचायत स्तर पर बैठे हुये कर्मचारियों द्वारा पूर्णरूप से पंचायतों के विकास कार्यो के नाम पर शासन की राशि की होली खेलते हुये विकास कार्यो की गति को मात्र कागजों पर चलाते हुये देखने मिल रहा है।

अज्ञात चोरों ने पार किये आठ खम्बों का बिजली तार

हरिभूमि न्यूज/सांईखेड़ा।

क्षेत्र में जिस तरह चोरी सहित अन्य घटनाये घटित होते हुये देखी जा रही है उसके चलते जहां आमजन दहशत में देखा जा रहा है तो दूसरी ओर पुलिस की सस्त कार्य प्रणाली उजागर होने से नही चूक रही है। क्योंकि जहां किसानों के खेतों में रखे हुये कृषि कार्य संबंधी सामग्री चोरी होना आम बात हो चुकी है। मगर अब तक चोरों द्वारा खम्बों पर लगे हुये बिजली तारों को भी नही छोड़ा जा रहा है। कुछ इसी प्रकार की सच्चाई बीते हुये दिनो बनबारी क्षेत्र के सूखा हार में देखने मिली है जहां पर अज्ञात चारों द्वारा आठ खम्बों का बिजली तार सहित अन्य सामग्री पार करते हुये बिजली विभाग से लेकर क्षेत्र के लोगों को चिंता में डाल दिया गया है। घटना के संबंध में सांईखेड़ा विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि मुझे जानकारी प्राप्त हुयी कि ग्राम बनवारी के सूखा तिराहा मोती साहू के खेत से लेकर 8 खम्बो के स्पान की पुरानी 33 केवी विद्युत लाईन के तार कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है मैने मौके पर जाकर देखा तो 8 खम्बो की स्पान विद्युत लाईन नही थी। इस संबंध मे बिजली अधिकारी द्वारा पुलिस ाि ने में लिखित आवेदन पेश करते हुये बताया है कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम/क्षेत्र ग्राम बनवारी के सूखा तिराहा मोती लाल साहू के खेत से लेकर 8 खम्बों के स्पान के 33 केवी विद्युत लाइन के तार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिए गये है। इस चोरी की घटना के कारण न केवल विभाग को आर्थिक हानि हुई है, बल्कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड रहा है। घटना को लेकर बिजली अधिकारी की शिकायत पर सांईखेड़ा पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है। मगर घटना को एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की खोज करने में असफल नजर आ रही है।

बेसहारा दृष्टिहीन वृद्वा की मदद के लिये वर्षा ने बेटी की तरह तो दिनेश से बेटे जैसा स्नेह देते हुये गोद में उठाने से भावुक लाचार बुजुर्ग महिला

हरिभूमि न्यूज। सांईखेड़ा।

पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में पुलिस के प्रति कुरूरता का आधार मानते हुये पुलिस के लिये बुरा भला कहने से नही चूकते है..? मगर पुलिस की सच्चाई पर नजर डाली जावे तो पुलिस अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हुये जहां लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये अपनी जान दांव पर लगाने में पीछे नही रहती है। वही लोगों की जिन्दगी बचाने के लिये सदा ही तत्पर रहती है। यह बात अलग है कि कभी कभी कुछ स्थितियाँ या फिर मजबूरियाँ इस तरह की बन की पुलिस को सख्त होना पड़ता है। मगर मजबूरी बस पुलिस की सख्ती आमजन के दिलों में बैठे जाती है। यदि पुलिस द्वारा आमजन के लिये मदद पहुंचाने की सच्चाई पर नजर डाली जावे तो वह उस समय लोगों की मदद के लिये नजर आती है जब लोग किसी व्यक्ति को हाथ लगाने की बात तो दूर उसके पास खड़ा होना तक उचित नही समझते है। मगर वहां पर पुलिस इस तरह के लोगों को मदद पहुंचाते हुये उनकी जिन्दगी को सुरक्षित बनाते हुये देखी जाती है। कुछ इसी प्रकार की सच्चाई बीते हुये दिवस सांईखेड़ा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम तूमडा में देखने मिली है। यहां पर एक दृष्टिहीन बेसहारा महिला को जब पुलिस की निर्भया टीम में शामिल एस आई वर्षा धानक व आरक्षक दिनेश पटैल मौके पर पहुंचे तो कई दिनों से गंदगी के बीच घिरी हुई महिला को जहां आरक्षक दिनेश पटैल द्वारा बेटे की तरह स्नेह देते हुये गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया तो दूसरी ओर एस आई वर्षा धानक द्वारा बेटी की तरह प्यार देते हुये कई दिनों से भूखी वृद्वा को अपने हाथों से भोजन खिलाया गया। इस सच्चाई को देखते हुये जहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आने से नही चूके। वही दूसरी ओर पुलिस की सख्ती के बाद मदद के लिये पुलिस की स्नेह पूर्ण कार्य प्रणाली ने एक अनूठी मिशाल पेश करने में कोई कसर नही छोड़ी गई है। बताया जाता है कि साँईखेड़ा की निर्भया मोबाइल को ग्राम तूमड़ा में एक असहाय वृद्ध महिला के दयनीय स्थिति में होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला की मदद कर भोजन, नए वस्त्र एवं सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था कराई पुलिस के अनुसार 11 मई 2026 को सूचना मिली थी कि ग्राम तूमड़ा में एक वृद्ध महिला बेहद खराब हालात में रह रही है और उसे तत्काल सहायता की जरूरत है। सूचना मिलते ही थाना साँईखेड़ा पुलिस निर्भया मोबाइल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि ग्राम पंचायत के पुराने भवन के बंद शटरनुमा कमरे में वृद्ध महिला खटिया पर असहाय अवस्था में पड़ी थीं। कमरे के चारों ओर गंदगी फैली थी। महिला दोनों आंखों से दृष्टिहीन थीं और शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि स्वयं उठने-बैठने और चलने-फिरने में भी असमर्थ थीं। ग्रामीणों एवं सरपंच पति से पूछताछ में महिला की पहचान सब्बो बाई पति स्व. रामरतन पटैल (लगभग 75 वर्ष), निवासी ग्राम तूमड़ा के रूप में हुई। वही वृद्वा के परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई सदस्य नहीं है और लंबे समय से वे निराश्रित अवस्था में जीवन बिता रही थीं। महिला की स्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल मानवीय पहल करते हुए जिला रायसेन के बाड़ी स्थित "टीम पहल सेवा आश्रम" से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस टीम ने वृद्ध महिला को गोद में उठाकर वाहन तक पहुंचाया, भोजन कराया, नए वस्त्र उपलब्ध कराए और निजी वाहन की व्यवस्था कर सुरक्षित आश्रय के लिए आश्रम भेजा गया। महिला उपनिरीक्षक वर्षा धाकड़, आरक्षक दिनेश पटैल एवं निर्भया मोबाइल स्टाफ ने वृद्ध महिला को सकुशल टीम पहल सेवा आश्रम, बाड़ी जिला रायसेन में भर्ती कराया, जहां अब उनकी समुचित देखभाल और उपचार किया जाएगा।

ग्रामीण सड़कों से निकल रहे भारी भरकम वाहनों के चलते टूट रही सड़क, आम लोगों की जान के लिए बना खतरा

हरिभूमि न्यूज/सांईखेड़ा।

जहां एक ओर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गांव गांव पक्की सड़कों का निर्माण तो किया जा रहा है, मगर वह सड़क निर्मित होने के चंद दिनों बात जिस प्रकार से टूट रही है उसका प्रमुख कारण एक है कि प्रभावशालियों के दौड़ रहे भारी भरकम डम्फरों की मार जहां यह सड़क सहन नही कर पा रही है। वही दूसरी ओर आम लोगों की जिन्दगी के लिए खतरा पैदा होने से भी नही बच पा रहा है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से गांव गांव प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क व मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जिन सड़को का निर्माण किया जाता है इन सड़कों को उसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है इन सड़कों से इस प्रकार के भारी वाहन तो निकलेगे ही नही सिर्फ किसानों के ट्रेक्टर ट्राली ही निकलेगे, मगर जिस प्रकार से इन ग्रामीण सड़को पर बड़े बड़े दस चाक वाले डम्फर दौड़ रहे है उसके चलते ग्रामीण सड़क चंद दिनों में ही टूटकर चकराचूर होने से नही बच पा रही है। जबकि गौर किया जावे तो बीते हुये कुछ वर्ष पहले तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा भी इस प्रकार से ग्रामीण सड़को से भारी भरकम डम्फर के दौड़ने संबंध प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये थें। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़को पर वोर्ड स्थापित किये जावे जिसमें इस बात को उल्लेख किया जावे कि यह सड़क कितनी क्षमता के वाहनों का भार सहन कर सकती है उससे अधिक क्षमता के वाहनों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मगर वर्तमान समय में देखने मिल रहा है कि शायद जिला स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर बैठे हुये अधिकारियों को इस बात से कोई लेना देना नही रह गया है ओर ग्रामीणों की सुविधाओं के लिये बनाई गई सड़को पर भारी भरकम स्थिति के दौड़ने वाले वाहनों को अधिकारियों द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा है। इस स्थिति के चलते जहां ग्रामीण सड़के लगातार टूटते हुये दिखाई दे रहे है।

म.प्र.शासन का लेख कराते हुए बगैर परमिट दौड़ रहे चार पाहिया वाहन

हरिभूमि न्यूज/ सालीचौका।

आबादी के बढ़ते दबाव के चलते पूरे जिले मे सड़कों पर दौडने वाले चार पहिया सवारी बाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इन वाहनों पर नियंत्रण के लिए नियम कायदे बने है, जिनका पालन कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है मगर विभागीय सुस्ती के कारण सड़कों पर बगैर परमिट के अनेक टैक्सी धडल्ले से चल रहे है, कभी कभार कागजी खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़नें वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है । मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन मे सवारियों का परिवहन करना सरा सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हें किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे है, वही दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व को भी हानी पहुंच रही है, देखने मे आ रहा है कि अधिकांश जीप, मार्शल, बुलेरो, स्कारपियों या उसे जैसे वाहन निजी कंपनियों में किराय पर सवारी ढोने के काम मे लगे हुए है, इस प्रकार वाहन मालिक टैक्स की राशि बचाकर अपने वाहनों को सवारियों के परिवहन मे लगा देते है और परिवहन विभाग कभी इसी जांच के लिए व्यापक अभियान नही छेड़ता, परिणाम स्वरूप ऐसे वाहन धडल्ले से चल रहे और इनकी संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है, जब कोई दुर्घटना होती है तब अधिकारियों से लेकर आम पब्लिक हाथ मलते रह जाती है, नगर में स्थित व क्षेत्र में स्थित अनेक कंपनियों में इसी प्रकार अधिकांश शासकीय विभागों मे निजी वाहनों को किराए पर लगाया गया है, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सरकारी दप्तर से आवश्यकता होने पर जो वाहन किराए पर लगाए जाएं उनका रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग मे टैक्सी वाहन के रूप मे होना अनिवार्य है, परिवहन विभाग के पास इन वाहनों पर कार्यवाही किये जाने की जानकारी नही मिली। शासन के आदेश की विभागीय अधिकारी विभाग भी इस दिशा मे उदासीनता प्रदार्शित कर रहा है।

खबर संक्षेप

तेज रफ्तार का कहर दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत तीन घायल

डिंडौरी। जिले में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महावीर गांव स्थित पालिटेक्निक कॉलेज के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कारोपानी निवासी करीब 35 वर्षीय शशिकांत पट्टा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।जानकारी के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रही थीं। इसी दौरान पालिटेक्निक कॉलेज के पास अचानक दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी तथा घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार जारी है। वहीं शशिकांत पट्टा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय मंत्री ने मां नर्मदा का किया पूजन-अर्चन

अमरकंटक। मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग की कैबिनेट मंत्री संपतिया उईके ने पवित्र धार्मिक एवं आध्यात्मिक तीर्थ नगरी अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा उद्गम स्थल में विधिवत दर्शन, पूजन एवं अर्चन किया। मंत्री श्रीमती उईके ने गहन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मां नर्मदा के पावन दरबार में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। इसके पश्चात उन्होंने अमरकंटक स्थित प्रसिद्ध अमरकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव का वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। नर्मदा मंदिर के पुजारी उमेश द्विवेदी बंटी महाराज ने मंत्री उईके का विधिवत रुद्राभिषेक कराया। कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उईके लगभग ढाई घंटे तक नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर में रहीं तथा मंदिर की धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता निभाई।

घायल पशुओं के उपचार पर संकट, नगरवासियों ने विभागीय लापरवाही पर उठाए सवाल

शहपुरा पशु चिकित्सालय में अव्यवस्था इमरजेंसी ड्रेसिंग सामग्री तक नहीं

शहपुरा। डिंडौरी जिले के शहपुरा स्थित पशु चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। नगरवासियों ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता का आरोप लगाया है। आरोप है कि अस्पताल में इमरजेंसी उपचार के लिए आवश्यक मलहम-पट्टी और ड्रेसिंग सामग्री तक उपलब्ध नहीं है, जिससे घायल पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा।जानकारी के अनुसार, हाल ही में एक घायल पशु को उपचार के लिए शहपुरा पशु चिकित्सालय लाया गया था। पशुपालकों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद चिकित्सक ने ड्रेसिंग के लिए पट्टी उपलब्ध न होने की बात कही। यह सुनकर पशुपालक और स्थानीय नागरिक हैरान रह गए। लोगों का कहना है कि जब अस्पताल में प्राथमिक उपचार की मूलभूत सामग्री ही नहीं होगी, तो आपातकालीन परिस्थितियों में पशुओं का इलाज कैसे संभव होगा। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, अस्पताल में पिछले कई दिनों से मलहम-पट्टी और ड्रेसिंग सामग्री का अभाव बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक इसकी पूर्ति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भीषण गर्मी और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच घायल पशुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे समय में पशु चिकित्सालय में इमरजेंसी सुविधाओं का अभाव गंभीर चिंता का विषय बन गया है। नगरवासियों ने यह भी सवाल उठाया है कि शासन पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर लाखों रुपये खर्च करता है, इसके बावजूद अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। लोगों का कहना है कि यदि किसी गंभीर रूप से घायल पशु को तत्काल उपचार की आवश्यकता पड़े, तो अस्पताल की यह लापरवाही उसकी जान के लिए खतरा साबित हो सकती है।स्थानीय नागरिकों ने पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने तथा अस्पताल में तत्काल आवश्यक दवाइयों और ड्रेसिंग सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। इस घटना ने शहपुरा पशु चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है।

आयुष्मान प्रोत्साहन राशि वितरण में गड़बड़ी डॉक्टर पर विभागीय जांच की अनुशंसा

शहपुरा। विकासखंड शहपुरा स्थित खंड स्तरीय चिकित्सालय में आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता की शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। जांच में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के संकेत मिलने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।मामले की जांच के लिए जिला स्तर पर गठित समिति में अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा, पेंशन अधिकारी, जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी एवं जिला आयुष्मान समन्वयक को शामिल किया गया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा है। जांच में पाया गया कि तत्कालीन मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी शहपुरा एवं वर्तमान में मेहंदवानी में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्येन्द्र परस्ते प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत होने के बावजूद अन्य चिकित्सकों की तुलना में कई गुना अधिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रहे थे। प्रतिवेदन के अनुसार ड्यूटी रोस्टर में नाम नहीं होने के बावजूद उन्होंने मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में राशि आहरित की।जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि डॉ. परस्ते ने मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में 30 प्रतिशत की दर से 7 लाख 1 हजार 992 रुपए 20 पैसे प्राप्त किए, जबकि नियमानुसार उन्हें 10 प्रतिशत की दर से केवल 2 लाख 33 हजार 997 रुपए 40 पैसे मिलना था। हालांकि, अपने जवाब में डॉ. परस्ते ने कहा कि वे मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिए 30 प्रतिशत राशि प्राप्त करना उचित था।जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक मातृत्व अवकाश पर रहने के बावजूद प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा वार्डबॉय के रूप में कार्य नहीं करने वाले कर्मचारी आशुतोष रजक के खाते में भी राशि हस्तांतरित की गई। कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद भी उनके खातों में राशि डाले जाने के तथ्य सामने आए हैं।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिमत में कहा गया कि जांच दल ने दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किए बिना प्राथमिक आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। वहीं डॉ. परस्ते के प्रतिउत्तर और जांच रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर विरोधाभास भी पाया गया।कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन, संबंधित पक्षों के जवाब और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अभिमत के आधार पर मामले में विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक मानी है। इसके चलते डॉ. सत्येन्द्र परस्ते के विरुद्ध विभागीय जांच की अनुशंसा की गई है। अंतिम निर्णय विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

डिंडौरी। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर सभाकक्ष में प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विभागीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजना अंतर्गत संचालित गतिविधियों और प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।बैठक में पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आगामी कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही योजना से लाभान्वित हो सकें।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी उप संचालक कृषि संजय जोशी परियोजना प्रबंधक आत्मा आरपीएस नायक एलडीएम रविशंकर सहायक संचालक कृषि अभिलाषा चौरसिया उप संचालक पशुपालन एचपी शुक्ला सहायक संचालक उद्यानिकी चन्द्रभान सैयाम मत्स्य विभाग से आरके चंदेल एनआरएलएम प्रबंधक अर्पणा पाण्डेय जिला प्रबंधक सहकारिता अशोक द्विवेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।अधिकारियों ने क्षेत्रीय स्तर पर संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए। बैठक के अंत में योजनाओं के बेहतर संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।

आत्मा योजना अंतर्गत कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

डिंडौरी । किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना वर्ष 2025-26 के तहत कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं अन्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों से विभिन्न स्तरों के कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।योजना के तहत जिला स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए जिले से 10 कृषकों का चयन किया जाएगा। चयनित कृषकों को 25 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं विकासखंड स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड से 5 कृषकों का चयन कर 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए चयनित कृषकों को 50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
विभाग ने बताया कि आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित विकासखंड कार्यालय के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करते हुए विकासखंड कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है।कृषक चयन के लिए न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को मुख्य फसलों की पिछले पांच वर्षों की उत्पादकता का विवरण देना होगा। मिट्टी परीक्षण कर स्वाइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करने पर 1 अंक तथा स्वाइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा अनुसार उर्वरकों के उपयोग पर 2 अंक दिए जाएंगे। एमपी किसान पोर्टल में पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है।विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में विकासखंड जिला अथवा राज्य स्तर का सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्राप्त कर चुके कृषकों की प्रविष्टि आगामी तीन वर्षों तक चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाएगी।यह पुरस्कार उन कृषकों को दिया जाएगा जो कृषि एवं समवर्गीय क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों को अपनाते हों नवाचार कार्य करते हों प्राकृतिक एवं जैविक खेती भूमि एवं जल संरक्षण तथा कृषि विपणन में उल्लेखनीय योगदान देते हों और अन्य कृषकों को प्रेरित करते हों।प्राप्त आवेदनों में से पात्र कृषकों का चयन शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति करेगी। समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। विभाग ने जिले के कृषकों से निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने की अपील की है।

जनपद अध्यक्ष बोले अधिकारी नहीं होने से बढ़ रहीं आम जनता की समस्याएं

करंजिया जनपद पंचायत में स्थाई सीईओ की मांग तेज

डिंडौरी। करंजिया जनपद पंचायत में पिछले करीब एक वर्ष से स्थाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम और जनपद सीईओ दोनों का प्रभार दिए जाने के कारण जनपद पंचायत के कामकाज प्रभावित होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।जनप्रतिनिधियों का कहना है कि एक साथ कई जिम्मेदारियां होने से प्रभारी अधिकारी जनपद पंचायत को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इसका असर पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने तथा प्रशासनिक लापरवाही जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा स्वच्छता अभियान सड़क निर्माण और पेयजल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यों में अपेक्षित गति नहीं दिखाई दे रही है। पंचायतों के नियमित निरीक्षण और योजनाओं की मॉनिटरिंग भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थाई और सक्रिय सीईओ की नियुक्ति जरूरी बताई जा रही है।जनपद पंचायत अध्यक्ष राजू सिंह उइे ने कहा कि स्थाई सीईओ नहीं होने से जनपद के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर अक्षय डिगरसे को एसडीएम बजाग और करंजिया जनपद पंचायत सीईओ का प्रभार दिया गया है। वहीं उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त कलेक्टर भारती मेरावी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कई स्थानों का प्रभार होने के कारण अधिकारी जनपद पंचायत करंजिया को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होने से क्षेत्रीय समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है और कुछ अधिकारी-कर्मचारी मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में जनपद सदस्यों के साथ कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से जल्द योग्य और स्थाई अधिकारी की पदस्थापना करने की मांग की है ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

एआई एप से जिले में होगी टीबी रोग की स्क्रीनिंग

डिंडौरी । टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान और "टीबी मुक्त भारत" अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक एआई तकनीक आधारित "केट" (कफ अगेंस्ट टीबी) एप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 मई 2026 को आयोजित हुआ जिसमें डॉ. प्रज्ञा दुबे और उनकी टीम ने जिले के सभी सीएचओ को एप के उपयोग की जानकारी दी।प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि "केट" एप के माध्यम से केवल खांसी की आवाज के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि व्यक्ति की खांसी सामान्य है या संक्रमणजनित। एप संभावित टीबी रोगियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर उन्हें तत्काल जांच के लिए चिन्हित करेगा जिससे समय पर उपचार शुरू किया जा सकेगा।विशेषज्ञों के अनुसार एआई आधारित यह तकनीक टीबी रोग की स्क्रीनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दो से तीन दिन की खांसी के विश्लेषण से ही संभावित संक्रमण की पहचान संभव हो सकेगी। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एप के संचालन और उपयोग की विस्तृत जानकारी भी दी गई।स्वास्थ्य विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस तकनीक के माध्यम से टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान कर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा "टीबी मुक्त भारत" के साथ-साथ "टीबी मुक्त डिंडोरी" अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

बिक रहे अमानक पानी पाउच, रुपए खर्च कर उपभोक्ता खरीद रहे बीमारियां ज्यादा मुनाफा के लिए दुकानदार भी अमानक पाउच की बिक्री पर देते जोर

संबंधित विभाग सोया नींद में

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

गर्मी की शुरूआत के साथ ही निरंतर बढ़ रहे जल संकट की समस्या को देखकर हर दिन पानी पाउच व बॉटल की नई-नई कंपनियां मार्केट में उतर रही है वहीं पीने के पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जिनसे कंपनी को मुनाफा होता है वहीं उपभोक्ता बिना कोई जांच पड़ताल किये इस पानी को खुले पानी से बेहतर समझ कर महंगी कीमतों मे पी रहे है जबकि हकीकत तो यह है कि खुले पानी से यह पानी भी कम खतरनाक नहीं है।जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे पीने के पानी का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है।

बढ़ते कारोबार को देखते हुए मुनाफा कमाने के लिए अमानक पानी पाउच बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी शुरू होते ही नगर के होटलों, किराना दुकान और छोटी बड़ी ठंडा की दुकानों पर स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे पानी के पाउचों की बिक्री तेज हो गई है। एक रुपए में बिकने वाले पाउच अब पांच रुपए में दो बेचे जा रहे हैं। पन्नी में बंद पानी कहने को तो आईएसआई मार्का वाला फिल्टर पानी है, लेकिन हकीकत में यह पानी स्थानीय स्तर पर पैक किया जा रहा है। बाजार में मिलने वाले अधिकांश पानी पाउच में न तो पैकिंग तारीख अंकित होती है न एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। यह पानी भले ही तात्कालिक रुप से लोगों के कंठ को तर कर राहत देने में मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन बाद में न जाने कितनी बीमारियों का कारण बन रही हैं। यह पानी पाउच खाद्य एवं औषधि विभाग से बिना अनुमति एवं नगरीय प्रशासन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराएं बिना ही बेचे जा रहे हैं। इन अधिकांश पाउचों में न तो वाटर प्लांट का पता लिखा है न ही इमेल पता होता है। फिर भी यह नकली पाउच बाजार में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। ऐसे पानी के उपयोग से पीलिया, टाइफाइड, अल्माइजर आदि जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है।
ब्रांडेड पानी पाउचों की तुलना में नगर में अमानक स्तर के बने पाउच काफी सस्ते दामों में दुकानदारों को बेचे जाते हैं। इसलिए दुकानदार अपने फायदे के चक्कर में लोगों को दूषित पानी पिलाकर स्वास्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रांडेड कंपनी के पानी पाउच की पैकिंग में 100 पाउच रहते हैं। वह दुकानदार को 75 से 80 रुपए में मिलती है जबकि नकली पानी पाउच की बोरी, जिसमें 100 पाउच होते हैं, अधिकतम 40 से 45 रुपए में मिल जाते है। पानी के पाउच प्लॉट पर मशीन के माध्यम से पैक करके बेचे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में नगर में अनेक स्थानों पर घरों में पानी बनाकर बेचा जा रहा है। जिनमें बाजार में मिलने वाली सफेद पॉलीथिन को खरीदकर उसमें पानी भरकर धागा से बांध दिया जाता है और फ्रिज में रखकर उसी पानी को बेच दिया जाता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे देशी पाउच की बिक्री ज्यादा हो रही है।
आधुनिक व फैशन की बढ़ते इस युग में जहां पानी पाउच का बोतलबंद हर जगह सुलभ होने की वजह से इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। वहीं फैशन की नजरिये में भी इसका प्रचलन आजकल शादी के मंडप, घरों में पार्टियां व छोटे-मोटे फंक्शन में अब लोग गिलासों में पानी पिलाना अपनी तौहीनी समझते है बोतलबंद पानी व पाउच अब फैशन के रूप में लोगों को भाने लगा है। इसी कारण जरूरत व आवश्यकता अनुसार लोग इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे है तो वहीं अपना रूतवा दिखाने का माध्यम बन कर रह गया है। दूसरी ओर लोगों को सुलभता से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्लास्टिक कंटेनर, बोतल एवं प्लास्टिक के पाउच भले ही लोगों के पास सुलभता से उपलब्ध हो जाते है लेकिन यही प्लास्टिक के कंटेनर हो या बोतल या फिर प्लास्टिक के पााउच जिसे पानी पीने के बाद उपभोक्ता सड़कों पर फेंक देते है जो पर्यावरण के लिये खतरा पैदा कर रहे है वहीं मूक बधिर जानवर खाकर काल के गाल में समा रहे है। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आईएसआई मार्का का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है, तभी बीआइएस विभाग इस संबंध में कार्रवाई करता है। जबकि बाजार में अमानक पानी पॉउच के संबंध में कार्रवाई का अधिकार प्रशासन व खाद्य और औषधि विभाग के जिम्मे होता है। इसके बावजूद विभाग द्वारा अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाने के चलते नगरवासियों को सदैव बीमारियों का डर बना रहता है। किसी भी कंपनी को पानी के पाउच निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा जारी लाइसेंस की जरूरत होती है। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अनुमति भी होना आवश्यक है। इसके अलावा पानी के पाउचों को पैकिंग तारीख दी जाती है।

हरिभूमि

नर्मदा भूमि

10

जबलपुर, गुरुवार 14 मई 2026

login : www.haribhoomi.com

करेली | तेंदूखेड़ा | श्रीधाम | सालीचौका | सुआतला | गाडरवारा | राजमार्ग | साईंखेड़ा | चीचली | करकबेल

296 करोड़ रुपये कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

माताओं-बहनों का सम्मान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

लाड़ली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपये की राशि अंतरित

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिये माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश शासन की सबसे बड़ी और प्रभावी योजनाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर की पावन धरती पर बहनों के बीच पहुंचकर ऐसा अनुभव हो रहा है मानो रक्षाबंधन, भाईदूज और दीपावली जैसे सभी पर्व एक साथ मनाए जा रहे हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में आयोजित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। साथ ही 296 करोड़ 34 लाख रुपये लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। रानी दुर्गावती के पराक्रम को नमन किया।

मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुंगवानी में कॉलेज खोलने की घोषणा की। साथ ही बेलखेड़ी-बरहटा-मुंगवानी मार्ग पर शेढ़ नदी पर पुल निर्माण, नरसिंहपुर में इंडोर-आउटडोर स्टेडियम उन्नयन, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान निर्माण तथा ग्राम बुढ़ैना में बांध निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खर्चों में नियंत्रण रखने की अपील की है। प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके काफिले में अब केवल 8 वाहन ही चलेंगे। उन्होंने आमजन से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने, पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खपत कम करने, रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करने तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की।

प्रतिभाओं का सम्मान

कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं आर्थिक सहायता वितरित की गई। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। वॉलीबॉल एवं क्रिकेट प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक सूट प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर 51 लाड़ली बहनों ने कलश यात्रा के माध्यम से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बहनों को साड़ी भेंट कर सम्मानित किया तथा कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। विभागीय प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र रही।

मातृशक्ति के कल्याण का संकल्प

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, श्रमिक और मातृशक्ति के कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के जीवन में आर्थिक आत्मविश्वास पैदा किया है और महिलाओं को परिवार तथा समाज में नई पहचान मिली है। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन विधायक गोटेगांव महेंद्र नागेश ने दिया। कार्यक्रम को प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत , सांसद चैधरी दर्शन सिंह, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने संबोधित किया। इस अवसर पर परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति काकोड़िया, तेंदूखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, विधायक सिवनी दिनेश राय, पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल, पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी, पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार, नरेश पाठक, श्रीमती साधना स्थापक, रामसनेही पाठक, संभागायुक्त धनंजय सिंह, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी - कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में लाड़ली बहने मौजूद थी।

आइशर ट्रक ने दो को रौंदा- शवों को रखकर सड़क पर बैठे ग्रामीण

तेंदूखेड़ा बुधवार को तेंदूखेड़ा गाडरवारा सड़क मार्ग पर भामा के आगे एक आइशर मालवाहक बाहन ने दो लोगों को रौंदते हुए भाग निकला।घटना की जानकारी लगते ही संपूर्ण क्षेत्र से बड़ी संख्या में मृतकों के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और गाडरवारा तेंदूखेड़ा सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना दोपहर साढ़े ग्यारह बजे के आस पास की बताई जा रही है। हमारे प्रतिनिधि को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम करोंदी निवासी लखनलाल पिता रघुवीर गौड़ 30 वर्ष एवं तेजराम पिता सेवाराम ठाकुर उम्र 40 साल एवं केशव पिता पूरन धानक उम्र 32 साल मोटरसाइकिल से करोंदी से तेंदूखेड़ा तरफ जा रहे थे कि काल बनकर सामने तरफ से आ रही एक आइशर मालवाहक बाहन ने सीधी टक्कर मार दी जिसमें दो लोगों तेजराम और लखन लाल की घटना स्थल पर दुखद मौत हो गई जबकि मोटरसाइकिल चालक केशव धानक को गंभीर चोटें आई हैं।घटना को जिसने भी देखा रोंगटे खड़े हो गए। घटना की जानकारी लगते लोगों ने सड़क मार्ग पर किया चक्का जाम कर दिया और जिले के किसी वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचने तक जाम बनाकर रखा।

आये दिन घटित हो रही घटनाएं

गाडरवारा तेंदूखेड़ा सड़क मार्ग पर आये दिन घटनाएं घटित होना चिंता का विषय बनीं हुई है।काफी घुमावदार मार्ग पर एन टी पी सी के बड़े बड़े कंटेनर

राख (फ्लाइएश)लेकर दिन रात अबाध गति से दौड़ते हैं।अभी तक छ मौतें हो चुकी है। लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उचित और ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

पीड़ित के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने रखी मांग

क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उक्त भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तथा पीड़ित परिवार के लोगों को तथा मुआवजा राशि दिलाये जावे। मृतकों की पत्नियों को रोजगार एवं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कराई जाये।दो दो लाख रुपए तत्काल प्रभाव से मुआवजा तथा दुर्घटना में संलिप्त बाहन एवं बाहन मालिक और चालक पर वैधानिक कार्यवाही और मुआवजा दिलाया जाये।

घटना स्थल पर पहुंची कांग्रेस की अध्यक्ष

घटना की सूचना मिलते ही जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पटेल के साथ साथ जनपद पंचायत चांवरपाठा के अध्यक्ष सोबरन सिंह ठाकुर तथा ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश पटेल के साथ वीरेंद्र सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

परिजनों को दो-दो लाख का मुआवजे का आश्वासन

लगभग पांच छः घंटे तक चक्काजाम लगे रहने और मुआवजा सहित विभिन्न मांगों का आश्वासन दिए जाने के उपरांत लोग माने मौके पर उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पूजा सोनी ने पीड़ित परिवारों को दो दो लाख रुपए दिलाये जाने का आश्वासन दिया।इस विषय को लेकर क्षेत्रीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि कि तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाये जाने की दिशा में कार्यवाही कराई जाएगी।

कालोनियों की बहार सुविधाओं की दरकार जनता परेशान

गोटेगांव=नगर में इन दिनों कालोनियों की बहार आई हुई हैं।अपने आवास के लिए लोगों को मजबूरी में इन वैध और अवैध कालोनियों में प्लॉट खरीदकर अपना आवास बनाने मजबूर होना पड़ रहा है लेकिन शासन अंध,मूक बना बैठा है जिसे इन कालोनियों में जनता के लिए सुविधाएं नहीं दिखती हैं इन कालोनियों में प्रमुख रूप से बिजली,सड़क,और पानी जैसी मूल भूत सुविधाओं की दरकार है फिर भी कालोनाइजर जमकर प्लॉट बेचकर अनचाहा मुनाफा कमा रहे हैं इन कालोनियों में प्लॉट बिकवाने के लिए दलाल भी सक्रिय रहते हैं परंतु खरीददार इन सुविधाओं को तरसते हुए दिखाई देते हैं।कई बार ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आई लेकिन प्रशासन ने कोई सख्ती और नियम कानून नहीं दिखाए जिससे कालोनाइजरों में शासन का खौफ नहीं है और अनचाहा व्यापार कर लाभ कमा रहे हैं आखिर मूल भूत सुविधाओं को नगर के कई कॉलोनी वासी कब तक तरसते रहेंगे ये विषय नगर में और कालोनियों के निवासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है।अधिकांश कालोनियों में बिजली लाइन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है इन कालोनियों के निवासियों ने एक एक किलोमीटर दूर से बिजली कनेक्शन लिया है जिससे आर्थिक बोझ भी इनको सहना पड़ा है वहीं बहुत सी कालोनियों में कालोनीवासियों के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है सड़कों पर पानी बह रहा है तो कहीं कच्ची नालियां हैं और जहां पक्की बनी है वो भी टूट फूट गई हैं इसके बाद भी कालोनाइजर अपनी कालोनियों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अनचाहे लाभ के चलते निवासियों को समस्त सुविधाएं देने से कतरा रहे हैं।इन कालोनियों में निवासियों को ग्रामीण क्षेत्र की याद आने लगी है पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो कच्ची नालियां होती थी वो इन कालोनियों में अपना दर्शन करा रही हैं पक्की नालियों का अभाव है।कालोनीवासियों का निस्तारि पानी नालियों के अभाव में कहां जाएगा ये गंभीर प्रश्न है।

हरिभूमि
समाचार ही नहीं, विचार भी

सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार 2026

प्रथम उपहार 1 कार

द्वितीय उपहार
3 नग बाईक

तृतीय उपहार
10 नग LED TV

चतुर्थ उपहार
5 नग फ्रीज

पांचवा उपहार
8 नग वासिंग मशीन

छठवां उपहार
15 नग गैस चूल्हा

सातवां उपहार
25 नग सिलिंग फैन

आठवां उपहार
40 नग ट्राली बैग

नवां उपहार
500 नग हॉट पॉट

दसवां उपहार
600 नग लंच बाक्स

ग्यारहवां उपहार
प्रत्येक प्रतिभागी को सांत्वना उपहार

नियम एवं शर्तें :- ❖ यह सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार योजना 1 मई 2026 से 31 दिसम्बर 2026 की अवधि के लिए है । ❖ हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं। ❖ महालक्की ड्रा. में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक सुनिश्चित उपहार जीतने का अवसर होगा। ❖ इस योजना अवधि में हरिभूमि समाचार पत्र में कुल 50 कूपन (35 सामान्य कूपन एवं 15 मास्टर कूपन) प्रकाशित किये जाएंगे। ❖ योजना में भाग लेने के लिये पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फार्मेट पर उपरोक्त अवधि के दौरान समाचार पत्र में प्रकाशित 50 कूपनों में से कुल 30 कूपन (20 सामान्य एवं 10 मास्टर कूपन) चिपकाने होंगे। ❖ फोटोकॉपी या कटे-फटे कूपन व फार्मेट मान्य नहीं होगे । ❖ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे। ❖ सुनहरा मौका सुनिश्चित उपहार योजना के विजेता को आयकर के नियम व शर्तें मान्य होगी । ❖ हरिभूमि निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ❖ किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा। ❖ चित्र में दर्शाए गए उपहार वास्तविक उपहार से भिन्न हो सकते हैं । ❖ हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते ।

आज ही हरिभूमि की प्रति बुकिंग करायें

हरिभूमि कार्यालय : 66/1, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई जिला जबलपुर

मो. 9479623424, 9340637789